



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]
No. 112]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 24, 2017/वैशाख 4, 1939
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 24, 2017/VAISAKHA 4, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2017

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

एसएसआर-10/2017

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित विस्कोस फिलामेंट यार्न के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

सं. 15/16/2016-डीजीएडी .— 1995 में और उसके बाद यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विस्कोस फिलामेंट यार्न (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

2. यतः प्राधिकारी ने 7 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना सं. 14/23/2004-डीजीएडी द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में मूल जाँच की शुरूआत की थी। अंतिम जाँच परिणाम दिनांक 4 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना सं. 14/23/2004-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किए गए और केन्द्र सरकार द्वारा 24 मई, 2006 की अधिसूचना सं. 45/2006 द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 15/8/2007 द्वारा एक मध्यावधि समीक्षा शुरू की गई जिसके अंतिम जाँच परिणाम दिनांक 22 मई 2009 की अधिसूचना सं. 15/8/2007-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किए गए और सीमाशुल्क अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई 2009 की अधिसूचना

सं. 81/2009-सीमाशुल्क द्वारा जारी की गई। पहली निर्णायक समीक्षा 25 फरवरी 2011 की अधिसूचना सं. 15/23/2010-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई और प्राधिकारी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम दिनांक 24 फरवरी 2012 की अधिसूचना सं. 15/23/2010-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किए गए। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 4 मई, 2012 की अधिसूचना सं. 23/2012-सीमाशुल्क द्वारा जारी किए गए।

3. यतः वर्तमान याचिका मै. केसोराम रेयान (सिगनेट इंडस्ट्रीज लि. की इकाई, जो केसोराम इंडस्ट्रीज लि. की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है) और मै. इंडियन रेयान (आदित्य विरला नुवो लिमिटेड की इकाई) (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के रूप में दायर की गई है, जिसमें लागू पाटनरोधी शुल्क को समय बढ़ाने की मांग की गई है। मै. सेंचुरी रेयान (सेंचुरी टैक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. का एक प्रभाग) ने याचिका का समर्थन किया है। याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान प्रयोजनों के लिए संगत वित्तीय सूचना प्रदान की है। याचिका नियम 5 के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से है।

क. शामिल देश

4. इस जाँच में शामिल देश चीन जन. गण. है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद '150 डेनियर तक विस्कोस फिलामेंट यार्न' है। इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 54 के अधीन विभिन्न सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 54033100, 54033200, 54033300, 54034110, 54034120, 54034130, 54034140, 54034150, 54034160, 54034170, 54034180 और 54034190 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। सीमा-शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक प्रकृति का है और जांच के दायरे पर किसी भी तरह से वाध्यकारी नहीं है।

6. प्राधिकारी ने मूल जाँच के अंतिम जाँच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया है,

'इस जाँच में विचाराधीन उत्पाद 150 डेनियर (और उसके +4 प्रतिशत अनुमत अंतर) तक के विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न हैं जिसमें 67 डेमिटैक्स से कम के मोनो फिलामेंट यार्न शामिल हैं जिन्हें विस्कोस फिलामेंट यार्न या वीएफवाई, रेयान फिलामेंट यार्न, आर्ट मिल्क यार्न, सेल्युलोज यार्न और 100 प्रतिशत विस्कोस से निर्मित सभी यार्न शामिल हैं जैसे डाइड यार्न, फ्लेटयार्न, माइक्रो फिलामेंट माइक्रोयार्न, ट्रिवस्टेड यार्न (एम्ब्राइडर्ड यार्न को छोड़कर) वीएफवाई के डबल/मल्टीपल प्लाई यार्न आदि शामिल हैं जब तक इस पैराग्राफ में विशेष रूप से बाहर न किया जाए (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है)।'

7. प्राधिकारी ने एम्ब्राइडर्ड यार्न के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार बताया

पिछले पाटनरोधी शुल्क के दायरे से बाहर रखे गए उत्पाद निम्नानुसार थे –

- i. एम्ब्राइडर्ड यार्न – यह स्पष्ट डाइड विस्कोस रेयान एम्ब्राइडर्ड धागा होता है।
- ii. सिलाई धागा
- iii. फर यार्न
- iv. अग्नि रोधी यार्न
- v. इंजीनियर्ड यार्न
- vi. एअर टैक्सनराइज्ड यार्न

'एम्ब्राइडर्ड यार्न/धागा' एक यार्न होता है जिसे विशिष्ट रूप से एम्ब्रायडरी और सुई से किए जाने वाले अन्य रूपों के लिए विनिर्मित या हाथ से बुना जाता है। यह एक समर्थित तैयार उत्पाद होता है जो एम्ब्रायडरी अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग हेतु तैयार रूप में होता है। एम्ब्रायडरी यार्न को डाइंग, रीलिंग, ट्रिवस्टिंग, हैंकिंग या कोर वाइंडिंग, तैयार उत्पाद की गुणवत्ता जाँच, ग्रेडिंग और रॉयर्न की पैकिंग की प्रक्रिया से उत्पादित किया जाता है।'

8. चूंकि वर्तमान जाँच निर्णयिक समीक्षा जाँच होने है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा पहले सम्पन्न जाँच और इस मामले में बाद में जारी किए गए स्पष्टीकरणों के समान रहेगा। प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या विचाराधीन उत्पाद के दायरे में किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। हितबद्ध पक्ष इस अधिसूचना में विहित समय सीमा के भीतर संगत सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं।

ग. समान वस्तु

9. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाठन के कारण जाँच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समतुरुप नहीं हैं परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं।

10. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पादों में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

11. मै. केसोराम रेयान और मै. इंडियन रेयान ने घरेलू उद्योग के अपेक्षित सूचना उपलब्ध की है। याचिकाकर्ता कंपनियों ने दावा किया है कि उन्होंने पीओआई के दौरान चीन से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग माने जाने के पात्र हैं। मै. सेंचुरी रेयान ने याचिका का समर्थन किया है। प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता कंपनियों को घरेलू उद्योग माना है और यह आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

निर्णयिक समीक्षा की शुरूआत

12. यतः प्रस्तुत किए गए विधिवत रूप से साक्षात्कृत आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाठनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा निर्णयिक समीक्षा जाँच की शुरूआत करते हैं ताकि संबद्ध देश से संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा की जा सके और इस बात की जाँच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क को हटाये जाने से पाठन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

च. जाँच अवधि

13. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ याचिका में जाँच अवधि अप्रैल 2015 – सितंबर 2016 (18 महीने) की है। तथापि क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2012- मार्च 2013, अप्रैल 2013- मार्च 2014, अप्रैल 2014- मार्च 2015 और जाँच अवधि की अवधि शामिल होगी।

तथापि, अपेक्षित विश्लेषण में और अधिक अद्यतन आकड़ों के लिए, प्राधिकारी ने 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 (12 महीने) की अवधि पर विचार किया गया है। क्षति जाँच अवधि पर विचार किया गया है और अप्रैल 2013- मार्च 2014, अप्रैल 2014- मार्च 2015, अप्रैल 2015- मार्च 2016 और जाँच अवधि का प्रस्ताव किया गया है।

छ. प्रक्रिया

14. वर्तमान निर्णयिक समीक्षा में मूल जाँच के लिए अधिसूचना सं. 14/03/2004 प्रकाशित मूल जाँच के अंतिम जाँच परिणाम और निर्णयिक समीक्षा जाँच और पहले समाप्त हुई निर्णयिक समीक्षा जाँच के लिए 24 फरवरी 2012 की अधिसूचना सं. 15/23/2010 के सभी पहलू शामिल होंगे।

15. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उक्त अनुरोध का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा।

अ. समय-सीमा

18. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

अ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप से अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए और उनके साथ उनकी सॉफ्ट कापियाँ होनी चाहिए।

21. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

22. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु, सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार का उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ठ. असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डा. इन्द्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

New Delhi, the 24th April, 2017

INITIATION NOTIFICATION

SSR – 10/2017

(Sunset Review)

Initiation of Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on imports of Viscose Filament Yarn, originating in or exported from China PR.

F. No. 15/16/2016-DGAD - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of "Viscose Filament Yarn" (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country).

2. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 14/23/2004- DGAD dated 7th April 2005. The final finding was published vide Notification No.14/23/2004-DGAD dated 4th April 2006 and definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 45/2006 - CUS dated 24th May 2006. A Mid-Term review was initiated by the Authority vide Notification No. 15/8/2007, the final finding for which was published by the Authority vide Notification 15/8/2007-DGAD dated 22nd May 2009 and customs notification was issued vide Notification No. 81/2009-CUS dated 13th July 2009. The First Sunset Review was initiated vide Notification No. 15/23/2010- DGAD dated 25th February 2011 and the final findings were published by the Authority vide Notification No.15/23/2010-DGAD dated 24th February 2012. Customs notification was issued by the Central Government vide Notification No. 23/2012 – CUS dated 4th May 2012.

3. Whereas, a petition has been filed by M/s Kesoram Rayon (Unit of Cygnet Industries Ltd, a wholly owned subsidiary of Kesoram industries Ltd.) and M/s Indian Rayon (a Unit of Aditya Birla Nuvo Limited) (*hereinafter referred to as Petitioners*), as the domestic industry for the product under consideration, seeking extension of antidumping duty in force. M/s Century Rayon (a division of Century Textiles and Industries Limited) has supported the petition . The petition is in the form and manner prescribed by the Designated Authority under Rule 5, containing relevant information for the present purposes.

A. Country involved

4. The country involved in this investigation is China PR.

B. Product under Consideration and Like Article

5. The product under consideration in the present investigation is "Viscose Filament Yarn upto 150 denier". The product is classified under Chapter 54 of the Customs Tariff Act under various Customs Sub-headings, Nos. 54033100, 54033200, 54033300, 54034110, 54034120, 54034130, 54034140, 54034150, 54034160, 54034170, 54034180 and 54034190. Customs classification is indicative in nature and not binding on the scope of the investigation.

6. The Authority described product under consideration as follows in the final findings of the original investigation,

"the product under consideration in this investigation is Viscose Rayon Filament Yarn up to 150 deniers (and +- 4% permissible variation thereof) including mono filament yarn of less than 67 decitex also known as viscose filament yarn or VFY, Rayon Filament Yarn, Art Silk Yarn, Cellulose Yarn or Rayon Yarn and includes all yarns made of 100% viscose yarns such as dyed yarn, flat yarn, microfilament micro yarn, twisted yarn (with the exclusion of embroidered yarn), doubled/ multiple ply yarn etc of VFY unless specifically excluded in this paragraph (also referred to as subject goods herein after).

7. The Authority issued a clarification with regard to embroidered yarn, wherein the Authority had stated, inter-alia, as follows

The products which were excluded from the scope of ADD earlier are as follows-

- i. Embroidered yarn - this is clearly "dyed viscose rayon embroidered thread"
- ii. Sewing thread,
- iii. Fur yarn,
- iv. Fire retardant yarn,
- v. Engineered yarn,
- vi. Air texturized yarn,

"Embroidered yarn/thread" is a yarn that is manufactured or hand spun specifically for embroidery and other forms of needlework. It is a finished product wound on support which is ready to use for embroidery applications. Embroidery Yarn is produced by the process of dying, reeling, twisting, hanking or core winding, finished product quality checking, grading and packing of raw yarn"

8. Since the present investigation is a sunset review investigation, the scope of the product under consideration is the same as that of the previously concluded investigation and subsequently issued clarification . The Authority shall consider whether the scope of the product under consideration requires any further clarification. The interested parties may provide relevant information within the time limits prescribed in this notification.

C. Like Article

9. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

10. Petitioners have claimed that there is no known difference in subject goods exported from subject country and that produced by the domestic industry. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc.

D. Domestic Industry & Standing

11. M/s Kesoram Rayon and M/s Indian Rayon have provided required information as domestic industry. Petitioner Companies have claimed that they have not imported the product under consideration from China during the POI and qualify to be treated as "domestic industry" within the meaning of Rules. M/s Century Rayon has supported the petition. The Authority has considered the petitioner companies as domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

E. Initiation of sunset review

12. In view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

F. Period of Investigation

13. The period of investigation (POI) in the petition is April 2015 – September 2016 (18 months) for the purpose of present investigation. The injury investigation period will however cover the periods April 2012-March 2013, April 2013-March 2014, April 2014 - March 2015 and the POI.

However, to make the required analysis on more updated data, the Authority has considered the period from 1st April, 2016 to 31st March 2017 (12 months) as the investigation period. The injury investigation period has been considered and proposed to cover the periods Apr'13-Mar'14, Apr'14-Mar'15, Apr'15-Mar'16 and the period of investigation.

G. Procedure

14. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original and sunset review investigation findings published vide Notification No. 14/03/2004 dated 4th April 2006 for the original investigation and Notification No. 15/23/2010 dated 24th February 2012 for the previously concluded sunset review investigation.

15. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

H. Submission of Information

16. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street, New Delhi – 110001

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

I. Time Limit

18. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

J. Submission of information on confidential basis

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a)marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.

21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

22. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

K. Inspection of public file

26. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

L. Non-cooperation

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr. INDER JIT SINGH, Designated Authority